

प्रेषक,

डी०एस० गर्बाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 19 नवम्बर, 2012

विषय:-जनपद गढ़वाल के कोटद्वार में कार्यमानक प्रयोगशाला के निर्माण हेतु 0.130 है० भूमि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (विधिक माप विज्ञान उत्तराखण्ड) को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र सं०-मैमो/11-नजूल-2012-13 दिनांक-12.06.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद गढ़वाल के कोटद्वार में कार्यमानक प्रयोगशाला के निर्माण हेतु आपके द्वारा संस्तुत/अनुमोदित ग्राम खूनीबड़ पट्टी मोटाढाक के खसरा संख्या-136क मध्ये 0.130 है० भूमि, वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या- 260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15-2-2002 में निहित प्राविधानों एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड के अधीन विधिक माप विज्ञान विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।
- 3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

५/

- 5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- 6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
- 7- प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
- 8- प्रस्तावित भूमि श्रेणी-6(1) अकृषक-जलमग्न भूमि नदी के रूप में दर्ज है, जिसका नियमानुसार श्रेणी परिवर्तन की अनुमन्यता/कार्यवाही किये जाने के उपरान्त ही भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही की जायेगी। इस प्रक्रिया में यह धारा-132 जमींदारी भूमि व्यवस्था अधिनियम एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में दिये गये निर्णय का भी संज्ञान लिया जाय।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी०एस० गर्बाल)
सचिव।

पृ०प०संख्या 2581 /समदिनांकित/2012

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून।
- 5- प्रभारी, मीडिया केन्द्र, सचिवालय देहरादून।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।